

केंद्रीय बैंकिंग चुनौतीपूर्ण स्थिति में (सेंट्रल बैंकिंग एंट क्रॉस रोड्स)*

श्री शक्तिकान्त दास

मैं 'केंद्रीय बैंकिंग चुनौतीपूर्ण स्थिति में' विषय पर आयोजित इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित होने और अपने कुछ विचार साझा करने में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जब हमारे समय का निर्णायक इतिहास लिखा जाएगा तो पूरी संभावना है कि केंद्रीय बैंकिंग की विकास यात्रा में वर्तमान दशक को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में माना जाएगा। कोविड-19 महामारी और उसके बाद लगातार चले भू-राजनीतिक संघर्ष के बाद केंद्रीय बैंक एक धुंधले दौर में कदम रख रहे हैं। केंद्रीय बैंकों को, अपने अस्तित्व की पाँच शताब्दियों में जो नहीं हुआ, आज एक ऐसे भविष्य का सामना करना पड़ रहा है जहाँ उनके अधिदेश, उनके कार्य और उनके प्रदर्शन, सभी कठोर जांच के दायरे में हैं।

ऐसे में, केंद्रीय बैंक अभूतपूर्व परिवर्तनों से गुजर रहे वातावरण में काम कर रहे हैं। जो संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं वे, भू-आर्थिक विखंडन से होने वाली बाधाओं; मजबूत औद्योगिक, व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं तथा महत्वपूर्ण खनिजों, मध्यवर्ती पदार्थों, संसाधनों और सेवाओं की उपलब्धता को पहले से ही नया आकार दे रही वित्तीय नीतियों; नई प्रौद्योगिकियों; और जलवायु परिवर्तन के साथ केंद्रीय बैंकिंग के संदर्भ को मौलिक रूप से बदलने की शक्ति रखते हैं। इस तेज़ी से बदलते माहौल में केंद्रीय बैंकों को न केवल ज्ञात अनिश्चितताओं से बल्कि अज्ञात अनिश्चितताओं से भी गुजरना होगा।

इसके बावजूद इन असाधारण परिस्थितियों में भी केंद्रीय बैंक नए रास्ते तलाश रहे हैं और वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में अपने अधिकारक्षेत्र और कार्यक्षेत्र को नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। वे सुरक्षा को मजबूत करते हुए, प्रौद्योगिकीय नवाचारों का लाभ उठाकर, इन घटनाओं को मात देने का प्रयास कर रहे हैं।

* भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित RBI@90 उच्च-स्तरीय सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का मुख्य संबोधन।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का हम 90वां वर्ष मना रहे हैं। 1935 में इसकी स्थापना के बाद से इसकी यात्रा घटनाओं से भरपूर रही है। कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से रिज़र्व बैंक भारत की प्रगति संबंधी आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां भारत की प्रगति के भी मील के पत्थर हैं। वर्तमान समय में और भविष्य की ओर देखते हुए दुनिया भर में हो रहे घटनाक्रम भारत को निरंतर प्रभावित कर रहे हैं और केंद्रीय बैंकिंग प्रबंधक के रूप में हमें चुनौती दे रहे हैं।

आज का सम्मेलन हमें केंद्रीय बैंकिंग की अब तक की यात्रा पर आत्मावलोकन करने और भविष्य में हम अपनी भूमिका को कैसे देखना और आकार देना चाहते हैं, इस पर विचार करने का अवसर देता है। आज अपने संबोधन में मैं ऐसे तीन क्षेत्रों पर संक्षेप में बात करना चाहूंगा जहां भविष्य में केंद्रीय बैंकिंग को फिर से परिभाषित किए जाने की संभावना है - मौद्रिक नीति; वित्तीय स्थिरता; और नई प्रौद्योगिकियां। वास्तव में ये मुद्दे आज के सम्मेलन में होने वाले विशिष्ट सत्रों के विषयों में से ही हैं। मेरे विचार मुख्य रूप से विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंकिंग के संदर्भ में होंगे।

मौद्रिक नीति

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) से पहले व्यापार चक्रों की तीन दशकों की संयमित अस्थिरता और मूल्य स्थिरता तथा निर्बाध संवृद्धि के साथ-साथ चलने से शायद केंद्रीय बैंकों को यह विश्वास दिला दिया कि मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ स्थायी रूप से स्थिर हैं। ऐसे लगने लगा था कि 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में आया मुद्रास्फीति संकट हमारे समय से पूरी तरह पीछे छूट गया है। उस अनुभव से प्रभावित होकर, केंद्रीय बैंकों ने 'अंतिम उपाय के ऋणदाता' की अपनी भूमिका को त्याग दिया और जीएफसी की प्रतिक्रिया के रूप अपनी वित्तीय प्रणालियों की रक्षा करने के लिए पहले उपाय के ऋणदाता बन गए। उन्होंने जीएफसी से की गई इस शुरुआत को जारी रखा और एक बार फिर कोविड-19 महामारी के दुनिया भर में फैलने पर जीवन और आजीविका की रक्षा और संरक्षण के लिए पहले उपाय के मददगार के रूप में अग्रिम पंक्ति में पहुँच गए। उन्होंने ब्याज दरों को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँचाया, लंबी अवधि सहित सभी क्षेत्रों

में ब्याज दरों को स्थापित करने के लिए अपरंपरागत नीतिगत उपाय किए और लंबी अवधि के लिए ब्याज दरों के कम रहने का आश्वासन दिया। यह 1990 के दशक तक प्रचलित मौद्रिक रहस्यवाद के दौर से एक असामान्य प्रस्थान था। यह स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंकिंग 21वीं सदी के विकास के अनुरूप विकसित हुई है।

महामारी के समय किए गए उपायों ने अर्थव्यवस्थाओं को अत्यावश्यक सहायता प्रदान की, लेकिन महामारी के बाद की संकट अवधि में आर्थिक गतिविधि की रक्षा करने में अपनाई गई आसान मौद्रिक नीति की सीमाएँ और कमियाँ स्पष्ट हो गईं। आज, केंद्रीय बैंकों पर उनके द्वारा किए गए उपायों के परिणामों के संबंध में आरोप लगाया जाता है। यह आरोप सही या गलत हो सकता है। कुछ केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए उपायों में जो नकारात्मक बात देखी जाती है, वह है मौद्रिक नीति संचालन में उनकी स्वतंत्रता के साथ समझौता किया जाना। हालाँकि, भारत की स्थिति अलग थी। हमारे अधिकांश चलनिधि उपायों को उनकी घोषणा के समय ही सुविचारित ढंग से प्रस्तुत किया गया था और उसी समय उनकी समाप्ति तिथियाँ भी निर्धारित कर दी गई थीं।

केंद्रीय बैंकों के सामने एक और चुनौती है जो काफी हद तक महामारी के समय दिए गए राजकोषीय सुविधाओं के कारण बढ़े हुए लोक ऋण से संबंधित है। इसके बाद राजकोषीय समेकन के लिए किए गए प्रयासों ने पर्याप्त गति नहीं पकड़ी। ऐसी स्थिति कई देशों में मौद्रिक नीति के लिए एक बड़ी समस्या बन रही है। महामारी के बाद वैश्विक लोक ऋण 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 93.2 प्रतिशत तक बढ़ गया और 2029 तक वह सकल घरेलू उत्पाद के 100 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है¹। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ऋण-जीडीपी अनुपात ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं जिससे उनकी स्थिरता और व्यापक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उनके नकारात्मक प्रभाव प्रसार के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं। कई अन्य देशों के केंद्रीय बैंक ऐसे विशाल लोक ऋणों को, चाहे-अनचाहे रूप से, वित्तपोषण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि केंद्रीय बैंकों के अधीन आने वाले क्षेत्र में ऋण का बोझ बढ़ रहा है जिससे मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नुकसान पहुँचाने और व्यापक आर्थिक स्थिरता कमजोर होने का खतरा है।

¹ आईएमएफ फिस्कल मॉनिटर, अप्रैल 2024।

उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) के केंद्रीय बैंकों के लिए मौद्रिक नीति से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दे एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उनके लिए त्रिविध समस्या है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था वित्तीय रूप से एक-दूसरे से, पहले से अधिक, जुड़ी हुई है। प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा की गई मौद्रिक नीति कार्रवाई पूंजी प्रवाह और विनिमय दरों में बड़े उतार-चढ़ाव पैदा करती है जिसका असर घरेलू चलनिधि और मुद्रास्फीति पर पड़ सकता है और अंततः वह वास्तविक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। हालांकि प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियाँ उनकी घरेलू मुद्रास्फीति-संवृद्धि स्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, फिर भी उनका बड़ा प्रभाव उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक कि अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। पूंजी प्रवाह के कारण व्यापार प्रवाह घटने से इन प्रसार प्रभावों के अधिक बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। स्वाभाविक रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं को इस बाहरी प्रवाह को प्रबंधित करने और उसके प्रतिकूल परिणामों को कम करने के लिए अपने नीतिगत ढांचे और निधि भंडार को मजबूत करना होगा।

वित्तीय स्थिरता

वित्तीय स्थिरता केंद्रीय बैंकों के अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय बैंक के उद्देश्य के रूप में मूल्य स्थिरता का होना हाल ही का विचार है। आज यह मत बन रहा है कि जीएफसी और उसके बाद महामारी के दौरान अपनाई गई 'लंबे समय तक कम' नीतियों ने वास्तविक अर्थव्यवस्था को समर्थन तो प्रदान किया लेकिन इसके अलावा वित्तीय आस्तियों की कीमतों में भी उछाल पैदा किया, जो वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में केंद्रीय बैंकों की भूमिका को फिर से प्रभावित कर रहा है। बेहद कम ब्याज दरों और अत्यधिक चलनिधि के बीच, लीवरेजिंग और जोखिम उठाने का काफी उपयोग किया गया, इतना कि जैसे भविष्य में यह सुविधा न रहने वाली हो। नतीजतन, जब यूक्रेन युद्ध के साए में 2022 में केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति में आए उछाल का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने ऐतिहासिक रूप से मौद्रिक नीतियों में सबसे आक्रामक और समन्वित कसावट के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा हुए, खासकर तब, जब ये जोखिम मार्च 2023 में कुछ देशों में बैंकिंग संकट और अगस्त और सितंबर 2024 में वित्तीय बाजारों में

बिकवाली में बदल गए। इन घटनाक्रमों ने एक बार फिर वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित और संरक्षित करने में केंद्रीय बैंकों की भूमिका को पटल पर ला दिया है, विशेषकर इस भूमिका में कि मूल्य स्थिरता की खोज में उन्हें वित्तीय स्थिरता के विचारों को कैसे ध्यान में रखना चाहिए?

अब मैं वित्तीय स्थिरता के लिए उभरते कुछ जोखिमों पर बात करूँगा। पहली बात तो यह है कि वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीतियों में भिन्नता है - कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक ढील है, तो कुछ में सख्ती, और कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं में ठहराव है। इससे पूंजी प्रवाह और विनिमय दरों में अस्थिरता आने की उम्मीद की जा सकती है जो वित्तीय स्थिरता को बाधित कर सकती है। हमने अगस्त की शुरुआत में जापानी येन में तेज वृद्धि देखी, जिसके कारण येन कैरी ट्रेड में भारी उलटफेर हुआ और दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में हलचल मच गई।

दूसरा, निजी ऋण बाजारों का तेजी से विस्तार हुआ है। इन बाजारों का विनियमन सीमित है। वे वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर सकते हैं, खासकर तब जब मंदी में उनका दबाव-परीक्षण नहीं किया गया हो।

तीसरा, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के उद्देश्य से बढ़ाए गए ब्याज दरों ने ऋण चुकता करने की लागत, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और आस्ति गुणवत्ता के लिए जोखिम बढ़ा दिया है। कुछ प्राधिकार क्षेत्रों में की गई आस्ति मूल्यांकन में वृद्धि वित्तीय बाजारों में फैल सकती है, जिससे और अधिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) की कीमतें घटने से छोटे और मध्यम आकार के बैंकों पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में उनके बहुत ज्यादा निवेश हैं। सीआरई, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआई) और व्यापक बैंकिंग प्रणाली के बीच परस्पर जुड़ाव से ऐसे जोखिमों बढ़ते हैं।

नई प्रौद्योगिकियाँ

हाल के वर्षों में भुगतान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-संचालित डिजिटलीकरण की लहर क्रांतिकारी रही है। एक ओर जहां अधिकांश नवाचार राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा भुगतान पर केंद्रित रहे हैं, सीमा पार भुगतान बाजार में भी काफी विस्तार हुआ है। सीमा पार कामगारों द्वारा भेजे जाने वाले धन की बड़ी मात्रा, पूंजी के

सकल प्रवाह का बढ़ता आकार और सीमा पार ई-कॉमर्स के बढ़ते महत्व ने इस वृद्धि में उत्प्रेरक का काम किया है।^{2,3} भारत सहित कई उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सीमा पार पीयर-टू-पीयर (पी2पी) भुगतानों के प्रयोग के लिए धन प्रेषण शुरुआती बिंदु हैं। हमारा मानना है कि इस तरह के धन प्रेषण के लिए लागत और समय को काफी कम करने की अपार गुंजाइश है।

भारत चौबीसों घंटे उपलब्ध रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली वाली कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यूएसडी, ईयूआर और जीबीपी जैसी प्रमुख व्यापारिक मुद्राओं में लेनदेन का निपटान करने के लिए आरटीजीएस का विस्तार करने की व्यवहार्यता द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से तलाशी जा सकती है। भारत और कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही तरीकों से सीमा पार जलद भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव को बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।⁴

भारत ने एक विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) विकसित की है जिसने सीमा पार भुगतान के लिए अपार संभावनाओं वाले उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल वित्तीय उत्पादों को विकसित करने की सुविधा प्रदान की है। भारत अब दुनिया के तीसरे सबसे सक्रिय स्टार्टअप इकोसिस्टम का केंद्र है जिसमें 140,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, सौ से अधिक यूनिकॉर्न और 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की निधि जुटाई गई है। डीपीआई में भारत के अनुभव का लाभ अन्य देश वैश्विक डिजिटल क्रांति में सुधार और शुरुआत करने के लिए उठा सकते हैं।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ (सीबीडीसी) एक और ऐसा क्षेत्र है जिसमें दक्षतापूर्वक सीमा पार भुगतान की सुविधा प्रदान करने की क्षमता है। भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिन्होंने थोक

² वैश्विक सीमा-पार भुगतान का मूल्य 2027 तक 250 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है (क्रॉस-बॉर्डर भुगतान | बैंक ऑफ इंग्लैंड)

³ वैश्विक सीमा-पार बी2सी ई-कॉमर्स बाजार जिसका मूल्य 2022 में 889 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, 2030 तक राजस्व में छह गुना से अधिक बढ़कर 5.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है (क्रॉस बॉर्डर बी2सी ई-कॉमर्स मार्केट साइज रिपोर्ट, 2030)

⁴ इनमें प्रोजेक्ट नेक्सस शामिल है, जो चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) और भारत के घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (आईपीएस) को आपस में जोड़कर सीमा-पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के तहत भारत द्वारा सिंगापुर, यूएई, मॉरीशस, श्रीलंका, नेपाल आदि के साथ सीमा-पार भुगतान जुड़ाव पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

और खुदरा सीबीडीसी दोनों शुरू की हैं। प्रोग्रामेबिलिटी, यूपीआई खुदरा जलद भुगतान प्रणाली के अलावा अंतर-संचालनीयता और दूरदराज के क्षेत्रों और वंचित वर्गों के लोगों के लिए ऑफ़लाइन समाधानों का विकास ऐसी कुछ मूल्यवर्धित सेवाएं हैं जिन पर हम अब अपने सीबीडीसी पायलट के हिस्से के रूप में प्रयोग कर रहे हैं।

भविष्य में सीमा पार भुगतान और क्रिप्टोकॉरेंसी से जुड़ी वित्तीय स्थिरता संबंधी गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए सीबीडीसी के लिए मानकों और अंतर-संचालन का सामंजस्य स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा। एक प्रमुख चुनौती यह हो सकती है कि संबंधित देश अपनी घरेलू आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रणाली बनाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि हम एक प्लग-एंड-प्ले प्रणाली विकसित करके इस चुनौती को दूर कर सकते हैं जिसमें भारत के अनुभव के अनुरूप प्रणाली को विकसित किया जा सकता है जिससे संबंधित देशों की संप्रभुता को भी बनाए रखा जा सकेगा।

यह सर्वमान्य है कि वित्तीय सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण से दुनिया भर में वित्तीय क्षेत्र की दक्षता बढ़ी है लेकिन साथ ही कई चुनौतियाँ भी पैदा हुई हैं जिनसे केंद्रीय बैंकों को निपटना होगा। उदाहरण के लिए, आधुनिक दुनिया में सोशल मीडिया की पहुंच गहरी हो गई है और ऑनलाइन बैंकिंग तक पहुँच व्यापक हो चुकी है जिसके चलते राशि का अंतरण कुछ ही क्षणों में जाता है। ऐसे में अफ़वाहें और गलत सूचनाएँ बहुत तेज़ी से फैल सकती हैं और चलनिधि दबाव पैदा कर सकती हैं। बैंकों को सोशल मीडिया क्षेत्र में सतर्क रहना होगा और अपने चलनिधि भंडार को भी मजबूत करना होगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकीय प्रगति ने वित्तीय संस्थाओं के लिए व्यवसाय और लाभ विस्तार के नए अवसर खोले हैं। लेकिन, ये प्रौद्योगिकियां वित्तीय स्थिरता के लिए भी जोखिम पैदा करती हैं। एआई पर अत्यधिक निर्भरता से संकेन्द्रण जोखिम पैदा

हो सकता है, खासकर तब जब बाजार पर कुछ ही तकनीकी प्रदाता हावी हों। इससे प्रणालीगत जोखिम बढ़ सकते हैं क्योंकि इन प्रणालियों में उत्पन्न विफलता या व्यवधान पूरे वित्तीय क्षेत्र में फैल सकते हैं। इसके अलावा, एआई के बढ़ते उपयोग से नए जोखिम पैदा होते हैं, जैसे कि साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों के प्रति संवेदनशीलता का बढ़ना। इसके अलावा एआई की जटिल रचना के कारण निर्णय लेने वाले एल्गोरिदम का लेखापरीक्षण या उसकी व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है। इससे बाजारों में अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को इन सभी जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त जोखिम शमन उपाय करने चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो बैंकों को एआई और बिगटेक से लाभ उठाना चाहिए, न कि उनको हावी होने देना चाहिए।

निष्कर्ष

कठिन परीक्षणों और उतार-चढ़ावों के बावजूद मौजूदा दशक में केंद्रीय बैंकिंग का दौर सफल रहा है। मौद्रिक नीति के क्षेत्र में केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को लक्ष्य के करीब लाने में सफल रहे हैं। पूर्व में आए बड़े वित्तीय संकट या मंदी स्थिति को टाला गया। केंद्रीय बैंक अब प्रौद्योगिकीय नवाचारों में सबसे आगे हैं और उन्हें सैंडबॉक्स, इनोवेशन हब और हैकथॉन के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं।

जैसा कि हम मौजूदा दशक की उच्च तीव्रता वाली घटनाओं और ब्लैक स्वान से निपट रहे हैं, सीखे गए सबक भविष्य के लिए एक रास्ता तय करने के लिए आज हमारे विचार-विमर्श का आधार बन सकते हैं। केंद्रीय बैंकों को सतर्क, अनुकूलनशील बने रहना चाहिए, जोखिमों का लगातार आकलन करते रहना चाहिए और समुत्थानशील बने रहना चाहिए। उन्हें जटिल चुनौतियों से निपटने, टिकाऊ विकास को बनाए रखने, मूल्य स्थिरता बनाए रखने और मजबूत और सक्रिय वित्तीय प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

धन्यवाद।